



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(15 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारत के लिए सऊदी अरब का महत्व
- सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से जुड़ गया
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
- स्किल इंडिया डिजिटल ऐप

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



भारत के लिए सऊदी अरब का महत्व:

संदर्भ:

- भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण भागीदार है, और भारत देश के वास्तविक शासक और राजा बनने की कतार में अगले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ने का कोई मौका नहीं गंवा रहा है।

चर्चा में क्यों है?

- सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान ने जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की, जो पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक भारत को जोड़ने वाली एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है और जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को टक्कर दे सकता है।

ADDRESS:



- सऊदी प्रिंस जी20 शिखर सम्मेलन के बाद राजकीय दौरें पर भारत में रहे और भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की पहली बैठक में मोदी के साथ सह-अध्यक्षता की।
- दोनों पक्षों ने आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और रणनीतिक भंडार के लिए एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी के लिए अपनी हाइड्रोकॉर्बन ऊर्जा साझेदारी को उन्नत करना और सऊदी निवेश में 100 अरब डॉलर के लिए एक संयुक्त कार्य बल बनाना शामिल है।
- उन्होंने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संभावना और भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, जिसका सऊदी अरब सदस्य है, के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में तेजी लाने पर भी चर्चा की।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब को भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया है।

दोनों देशों के मध्य बढ़ता संबंध:

- दोनों देशों ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, और भारत सरकार का मानना है कि उनके बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं जो सदियों से चले आ रहे उनके सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं।
- जनवरी 2006 में सऊदी किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा रिश्ते में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। शाही यात्रा के परिणामस्वरूप दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 2010 में रियाद घोषणा हुई, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया।
- अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की रियाद यात्रा ने राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भावना को प्रदर्शित किया। किंग सलमान ने प्रधानमंत्री को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किंग अब्दुलअजीज़ सैश से सम्मानित किया, जो दर्शाता है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- फरवरी 2019 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद की भारत यात्रा ने इस गति को और आगे बढ़ाया। यह घोषणा की गई थी कि सऊदी अरब भारत में लगभग 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने के लिए सऊदी अरब का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2019 में फिर से रियाद का दौरा किया। यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत-सऊदी संबंधों को चलाने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की।
- इस रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) में अब राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग और अर्थव्यवस्था और निवेश पर अलग-अलग उप-समितियां हैं।

दोनों के मध्य रणनीतिक संबंध के स्तंभ:

- भारत के लिए, सऊदी अरब के साथ रणनीतिक संबंधों के चार प्रमुख तत्व हैं।

ADDRESS:



• आर्थिक जुड़ाव:

- भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है; सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 52.76 बिलियन डॉलर, जो 23% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के कुल व्यापार में सऊदी अरब के साथ व्यापार का हिस्सा 4.53% था।
- जनवरी 2022 तक, 2,783 भारतीय कंपनियां संयुक्त उद्यम/100% स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में सऊदी अरब में पंजीकृत थीं, जिनका वहां लगभग 2 बिलियन डॉलर का निवेश था।
- भारत में सऊदी का प्रत्यक्ष निवेश \$3.15 बिलियन (मार्च 2022 तक) था। सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष (पीआईएफ) ने सॉफ्टबैंक विजन फंड के माध्यम से कई भारतीय स्टार्टअप जैसे Delhivery, FirstCry, Grofers, Ola, OYO, Paytm, और PolicyBazaar में निवेश किया है।
- प्रमुख प्रस्तावित निवेशों में महाराष्ट्र में \$44 बिलियन का 'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट' है, जिसे सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और एक भारतीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम निगम शामिल हैं।

ADDRESS:



• ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग:

- सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भागीदार है, और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसका तीसरा सबसे बड़ा कच्चे और पेट्रोलियम उत्पाद स्रोत था।
- भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब से 39.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल का आयात किया, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 16.7% है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब से भारत का एलपीजी आयात 7.85 एमएमटी और इसके कुल पेट्रोलियम उत्पाद आयात का 11.2% था।

• रक्षा साझेदारी:

- हाल के वर्षों में रक्षा साझेदारी में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है।
- भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक नौसैनिक सहयोग है, और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, अल मोहम्मद अल हिंदी के दो संस्करण अब तक संपन्न हो चुके हैं।
- दोनों पक्ष रक्षा उद्योगों और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी निकटता से सहयोग करते हैं।

ADDRESS:



- **सऊदी अरब में भारतीय समुदाय:**

- सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की संख्या 24 लाख से अधिक है, जिसे सऊदी अरब के विकास में योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है और इसे दोनों देशों के बीच एक जीवंत पुल के रूप में देखा जाता है।
- संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारतीय पक्ष ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की उत्कृष्ट देखभाल के लिए सऊदी पक्ष को धन्यवाद दिया।

आतंकवाद का मुद्दा:

- भारत और सऊदी अरब ने आतंकवाद और इसके वित्तपोषण से निपटने के क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है।
- संयुक्त वक्तव्य में *“दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद, अपने सभी रूपों में, मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। वे इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी कारण से आतंकवादी कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद को किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया”*।
- दोनों पक्षों ने सभी देशों से अन्य देशों के खिलाफ आतंकवाद के इस्तेमाल को अस्वीकार करने, जहां भी मौजूद है वहां आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और आतंकवाद के अपराधियों को तेजी से न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया।

ADDRESS:



दोनों के संबंधों में MBS का महत्व:

- प्रधानमंत्री, नामित होने के बाद, जो पारंपरिक रूप से राजा द्वारा धारण किया जाने वाला पद है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया है।
- अपने विज़न 2030 के माध्यम से, एमबीएस ने खुद को सऊदी अरब के प्रमुख सुधारक के रूप में स्थापित किया है।
- उन्होंने देश के अति-रूढ़िवादी समाज में महत्वपूर्ण बदलाव सुनिश्चित किए हैं, जहां महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला है, और जहां सिनेमाघर खोले गए हैं, विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया जाता है, और पॉप सितारों और हाई-प्रोफाइल खेल मैचों की मेजबानी की गई है।
- लेकिन उनकी छवि आलोचकों के प्रति निर्दयी होने की है।
- एमबीएस ने चीन के साथ बातचीत की है, वह ईरान और इजरायल के साथ मेल-मिलाप की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अब अमेरिका, भारत और यूरोप के साथ सऊदी साझेदारी को भी मजबूत कर रहे हैं।
- भारत के साथ रणनीतिक रूप से जुड़े रहने के बावजूद रियाद अभी भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



सर्वोच्च न्यायालय 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड' से जुड़ गया:

मामला क्या है?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 14 सितंबर को घोषणा की कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG)' के साथ 'ऑनबोर्ड' है, जिसका अर्थ है कि लोग अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के संबंध में वास्तविक समय डेटा प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्य न्यायमूर्ति की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की, और कहा कि प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और देश में न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में मजबूती होगी।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



NJDG पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को शामिल होने से लाभ:

- अदालत की 'ओपन डेटा पॉलिसी' के तहत NJDG पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को शामिल करना न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक कदम है।
- NJDG-SCI (भारत का सर्वोच्च न्यायालय) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी में दीवानी और आपराधिक मामलों की वर्तमान पेंडेंसी, पिछले महीने में मामलों को दाखिल करना और निपटान, तीन-न्यायाधीशों, पांच-न्यायाधीशों और यहां तक कि नौ जजों की बेंच के समक्ष लंबित मामलों की संख्या शामिल होगी।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पोर्टल पर शामिल होने के साथ, ई-कोर्ट परियोजना का प्रमुख प्रोजेक्ट चक्र पूरा हो गया है। अब हमारे पास NJDG पोर्टल पर भारतीय न्यायपालिका के सभी तीन स्तर हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) क्या है?

- NJDG 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है जिसे 'ईकोर्ट प्रोजेक्ट' के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से NJDG में शामिल हो चुके हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय भी जुड़ गया है। इससे याचिकाकर्ताओं को मुकदमों से जुड़ी जानकारी तक आसान पहुंच की सुविधा मिल रही है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से लाभ:

- सर्च तकनीक का उपयोग करते हुए 'ई-कोर्ट' सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वर्तमान में वादकारी 23.81 करोड़ से अधिक मुकदमों और इन कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- NJDG, मुकदमों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मुकदमों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है।
- यह मुकदमों के निपटान में देरी को कम करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में मदद करता है और लंबित मुकदमों को कम करने में मदद करता है।
- उल्लेखनीय है कि NJDG को भारत सरकार की 'व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business)' पहल के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले:

- अब तक, 2023 में शीर्ष अदालत में कुल 64,854 पंजीकृत मामले और 15,490 अपंजीकृत मामले (रजिस्ट्री द्वारा निपटाए जाने बाकी) लंबित हैं।
- एनजेडीजी पर सुप्रीम कोर्ट के पेज से पता चलता है कि 583 तीन जजों वाली बेंच के मामले, 288 पांच जजों वाली बेंच के मामले, 21 सात जजों की बेंच और 135 (उनमें से सभी सिविल) नौ जजों की बेंच के संदर्भ लंबित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में दायर मामलों की संख्या 5,412 थी और पिछले महीने निपटाए गए मामले 5,033 थे।
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह लंबित मामलों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों की और अधिक विशेष पीठें गठित करेंगे।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):

संदर्भ:

- भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी की विशाल क्षमता को समझते हुए इस क्षेत्र के प्रणालीगत विकास की शुरुआत की।
- इन प्रयासों से 2020 में भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र शुरू किए गए सुधारों के कारण एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था लेकिन कोविड-19 महामारी ने प्रगति को रोकने का खतरा पैदा कर दिया था।



- हालांकि, प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा करके इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। सितंबर 2020 में

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के लिए ₹20,050 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई, जो भारतीय मत्स्य पालन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

- सरकार ने हाल ही में PMMSY के तहत एक उप योजना के रूप में ₹6,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिससे पिछले नौ वर्षों में मत्स्य पालन में कुल निवेश ₹38,500 करोड़ से अधिक हो गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) क्या है?

- भारत सरकार का मत्स्य पालन मंत्रालय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू कर रहा है - मत्स्य पालन और मछुआरे के कल्याण सहित क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना।
- PMMSY को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।
- इसने प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की: समुद्री मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मछुआरों का कल्याण, बुनियादी ढांचा और फसल

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



उत्पादन के बाद का प्रबंधन, ठंडे पानी में मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन और समुद्री शैवाल की खेती, अन्य।

लॉन्च के बाद से इसकी अब तक क्या उपलब्धि रही है?

- तीन साल पूरे होने पर, PMMSY ने पारंपरिक जल से अंतर्देशीय मत्स्य पालन को सफलतापूर्वक खींच लिया है, और प्रौद्योगिकी को शामिल किया है, जिससे कई प्रतिभाशाली और उद्यमशील युवाओं को मत्स्य पालन में उद्यम करने के लिए प्रेरणा मिली है।
- PMMSY ने गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विस्तार करने में भी मदद की है। लगभग 20,000 हेक्टेयर ताजा तालाब क्षेत्र को अंतर्देशीय जलीय कृषि के अंतर्गत लाया जा रहा है, और यहां तक कि भूमि से घिरे हरियाणा और राजस्थान में भी, किसान जलीय कृषि के माध्यम से अपनी खारी बंजर भूमि को सफलतापूर्वक तालाब में परिवर्तित कर रहे हैं।
- PMMSY ने मछुआरा महिलाओं को सजावटी मत्स्य पालन, मोती संस्कृति और समुद्री शैवाल की खेती जैसे लाभकारी विकल्प और वैकल्पिक आजीविका का पता लगाने के लिए सशक्त बनाया है।

ADDRESS:



- तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में हाल ही में लॉन्च किया गया ₹127 करोड़ का समुद्री शैवाल पार्क वास्तव में मोदी सरकार का एक अग्रणी कदम है।
- भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में गिना जाता है, और दुनिया में सबसे बड़ा झींगा निर्यातक भी है।
- भारतीय मत्स्य पालन उत्पादन (2022-23 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 174 लाख टन) और निर्यात आय अब तक के उच्चतम स्तर पर है।
- 2014 के बाद से संचयी मछली उत्पादन पिछले 30 वर्षों के मछली उत्पादन से कहीं आगे है। झींगा उत्पादन 2013-14 में 3.22 लाख टन से 267% बढ़कर 2022-23 में 11.84 लाख टन हो गया।
- भारत का समुद्री खाद्य निर्यात भी 2013-14 में ₹30,213 करोड़ से दोगुना होकर 2022-23 में ₹63,969 करोड़ हो गया।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



स्किल इंडिया डिजिटल ऐप:

चर्चा में क्यों है?

- केंद्र ने 13 सितंबर को औपचारिक रूप से स्किल इंडिया डिजिटल ऐप लॉन्च किया, जो अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों और नौकरी लिस्टिंग के लिए लिस्टिंग को एक साथ लाता है।
- ऐप को अप्रैल में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था, और फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।

स्किल इंडिया डिजिटल ऐप की विशेषताएं क्या हैं?

- पाठ्यक्रम पूरा होने के सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र जारी करने और नौकरी आवेदकों और पाठ्यक्रम लेने वाले लोगों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित सीवी उत्पन्न करने के लिए इस ऐप को डिजिलॉकर और आधार से जोड़ा जाएगा।
- स्किल इंडिया डिजिटल ऐप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल; ईश्रम पोर्टल, असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए बनाया गया; नेशनल करियर सर्विस, नौकरी चाहने वालों के लिए 2015 में सरकार

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



द्वारा शुरू की गई एक पांच साल की परियोजना, और ASEEM नौकरी निर्देशिका से जुड़ा है।



- इस ऐप को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित किया गया था।

महत्व:

- कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सूचना प्रौद्योगिकी ने कहा कि “जब हम डिजिटल कौशल के बारे में बात करते हैं, तो इस चर्चा के दो घटक होते हैं: एक है डिजिटल डोमेन के लिए कौशल,... और दूसरा सवाल यह है कि आप डिजिटल रूप से कैसे कौशल हासिल करते हैं।”

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- श्री चन्द्रशेखर ने कहा कि यह ऐप दोनों रूपों, कौशल पर पाठ्यक्रम वितरित करने और संभावित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को एक साथ लाने के लिए डिजिटल मैचमेकिंग का उपयोग करने, में मदद करेगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC):

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 31 जुलाई 2008 को स्थापित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।
- इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में की गई थी।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC की 49% शेयर पूंजी है, जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% शेयर पूंजी है।
- इसका उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, यह स्केलेबल और लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठन पहल बनाने के लिए धन मुहैया कराता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)